I, therefore, urge upon the Union Minister to kindly sanction these works immediately.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I also want to associate myself with what the hon. Member has mentioned.

Demand for Central Assistance to solve shortage of electricity supply in Madhya Pradesh

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इसमें कोई दो मत नहीं कि समग्र रुप से पूरे देश में ही विद्युत कमी की समस्या है। यह समस्या अलग-अलग राज्यों में कमोबेश अलग-अलग हो सकती है, लेकिन मेरे गृह राज्य मध्य प्रदेश में बिजली की भारी कमी है जिससे राज्य में घरेलू उपयोग के साथ लघु उद्योगों, घरों में ही किए जाने वाले छोटे-मोटे धंधों, मझोले एवं बड़े उद्योगों और किसानों की फसल के उत्पादन प्रभावित हो रहे हैं।

सामान्य उपभोक्ताओं को विद्युत कमी से जहां असुविधा, परेशानी है, वहीं, राज्य के राजस्व से जुड़ी गतिविधियां भी ठप हो रही हैं।

अप्रैल, 2005 को मध्य प्रदेश राज्य को वास्तविक विद्युत आपूर्ति 3037 मेगावाट की आवश्यकता को विरुद्ध मात्र 2284 मेगावाट की गई। इसी प्रकार से पीक डिमांड के समय 5248 मेगावाट की आवश्यकता के विरुद्ध 3942 मेगावाट की उपलब्धता रही यानी 1306 मेगावाट विद्युत की कमी रही है। इसका असर प्रत्यक्ष रूप से बाजारों और औद्योगिक संस्थानों में देखा जा सकता है। उत्पादन प्रभावित होने से राज्य के राजस्व में भी कमी आई है। गांवों में किसानों की हालत खराब होने से उनमे आकोश है, उनके टयूबवैल बंद पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योग भी डांवाडोल है। विद्युत की कमी होने से राज्य के समक्ष भी कटौती के सिवाय और कोई चारा नहीं है और इस कटौती से बौखलाई जनता का सारा गुस्सा राज्य के शासन तंत्र और वितरण एजेंसी पर उतर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस समय किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की बिजली प्रतिदिन खरीद कर आपूर्ति कर रही है।

अतः विद्युत की भारी कमी की समस्या के समाधान के लिए मैं केन्द्र सरकार पुरजोर अनुरोध करती हूं:-

7. राज्य के पूराने बिजली जेनरेटिंग यूंनिटों के आधुनिकीरण के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

8. राज्य में केन्द्र सरकार नए जेनरेटिंग यूनिटों की स्थापना करे तथा वर्तमान में स्थापित किए जा रहे यूनिटों को समय से पूरा किया जाए।

9. पूर्वी क्षेत्र के एन.टी.पी.सी. स्टेशनों से प्रदाय की जा रही केन्द्रीय पुल की अनावंटित ऊर्जा की कटौती को पुनः बहाल करते हुए पूर्ववत् 350 मेगावाट की जाए। आज की तिथी में पूर्वी क्षेत्र केन्द्रीय पूल से मात्र 175 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रही है।

राज्य में परमाणु ताप बिजली घर की स्थापना की जाए।

मुझे आशा है कि इन उपायों के पश्चात् मध्य प्रदेश की बिजली की सप्लाई में काफी सुधार हो पाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Shri Yashwant Sinha, not here. Dr. Gyan Prakash Pilania.

Demand to take timely measures to avoid Energy Crisis in the Country

DR. GYAN PRAKASH PILANIA(Rajasthan): Sir, the Paris-based agency, IEA, was set up after the 1973-74 Arab oil embargo to oversee Western Energy needs.

On 7th November, 2005, the International Energy Agency warned that the world must change its energy habits or struggle with choking fumes, runaway oil demand and a growing dependence on volatile West Asia for fuel. In its World Energy Outlook, the IEA said that energy demand and green house gas emissions will soar by more than 50 per cent by 2030 if consumers keep burning oil unchecked. That would blow a hole in the Kyoto protocol aimed at cutting developed nations' emissions five per cent below 1990 levels by 2008—12.

To keep pace with the booming demand over the next 25 years, top producer Saudi Arabia and its neighbours would have to spend an annual @56 billion on rigs and refineries or oil prices will rise. Higher investments on oilfields would be required to satisfy consumers' thirst for fuel. Failure to spend enough over the next 25 years could slap an extra $13 a barrel on the projected oil price.